

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण में सामुदायिक रेडियो की भूमिका: मध्य भारत का अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE



Author

डॉ. विनय कुमार

सहायक आचार्य

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

ख्वाज़ा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय

लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

भारत में ग्रामीण आजीविका मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वनोपज और लघु उद्यमों पर आधारित है। मध्य भारत विशेषकर मध्य प्रदेश और झारखंड में सूचना, तकनीकी परामर्श और बाज़ार संपर्क की कमी ग्रामीण विकास में बाधक तत्व रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में सामुदायिक रेडियो सहभागी संचार के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का प्रभावी उपकरण बनकर उभरा है। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्य भारत के चयनित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों किसान वाणी सिरोंज, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम तथा रेडियो विकल्प के संदर्भ में ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन गुणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें अंतर्वस्तु विश्लेषण, अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार तथा उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया। निष्कर्षतः पाया गया कि सामुदायिक रेडियो न केवल कृषि तकनीक के प्रसार में सहायक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा सामाजिक पूंजी

निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक रेडियो स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक अनुभवों को मंच प्रदान कर ग्रामीण समाज में संवाद और सहभागिता की संस्कृति को सुदृढ़ करता है। यह माध्यम सरकारी योजनाओं, बाज़ार भाव तथा मौसम संबंधी सूचनाओं को सरल भाषा में प्रसारित कर किसानों के निर्णय-निर्माण को भी प्रभावित करता है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि सामुदायिक रेडियो सामाजिक विश्वास और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है, जिससे दीर्घकालिक ग्रामीण विकास की संभावनाएँ सशक्त होती हैं।

मुख्य शब्द

सामुदायिक रेडियो, ग्रामीण आजीविका, सहभागी संचार, कृषि विस्तार, मध्य भारत.

प्रस्तावना

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है (भारत की जनगणना, 2011)। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण आजीविका का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन तथा इससे संबद्ध गतिविधियाँ हैं; किंतु कृषि क्षेत्र अनेक संरचनात्मक चुनौतियों जैसे वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, तकनीकी जानकारी का अभाव, बाज़ार अस्थिरता, उत्पादन लागत में वृद्धि तथा ऋण-संकट से निरंतर प्रभावित होता रहा है। इन चुनौतियों के कारण किसानों की आय में अनिश्चितता बनी रहती है और आजीविका की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से मध्य भारत के

राज्यों में, जहाँ सिंचाई सुविधाएँ सीमित हैं और संसाधनों की उपलब्धता असमान है, सूचना एवं तकनीकी मार्गदर्शन की कमी ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को धीमा करती है।

विकास संचार की अवधारणा के अंतर्गत संचार माध्यमों को सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता निर्माण और व्यवहार परिवर्तन के प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जाता है (Melkote - Steeves, 2015)। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी है। सामुदायिक रेडियो इस संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह स्थानीय स्वामित्व, स्थानीय भाषा और स्थानीय सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसके माध्यम से प्रसारित सामग्री समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप होती है, जिससे संदेशों की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता बढ़ जाती है।

मध्य भारत के संदर्भ में यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सामुदायिक रेडियो वास्तव में ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण में ठोस और मापनीय योगदान दे रहा है। क्या यह केवल सूचना प्रसारण तक सीमित है, या फिर किसानों के व्यवहार, निर्णय-निर्माण और आय स्तर में भी परिवर्तन ला रहा है? प्रस्तुत शोध इसी मूल प्रश्न का विश्लेषणात्मक उत्तर खोजने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सामुदायिक रेडियो किस प्रकार कृषि तकनीक, बाज़ार सूचना, सरकारी योजनाओं और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित ज्ञान का प्रसार कर ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मध्य भारत में चयनित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
2. कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सूचना प्रसार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
3. ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के आयामों की पहचान करना।
4. सहभागी संचार सिद्धांत के संदर्भ में सामुदायिक रेडियो की भूमिका को समझना।

साहित्य समीक्षा

सामुदायिक रेडियो की अवधारणा लैटिन अमेरिका में 1940 के दशक में उभरी, जहाँ इसे सामाजिक न्याय, वैकल्पिक संचार और सामुदायिक सहभागिता के प्रभावी साधन के रूप में विकसित किया गया (Fraser - Restrepo-Estrada, 2001)। वहाँ यह माध्यम हाशिए पर स्थित समुदायों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने तथा सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए प्रयुक्त हुआ।

भारत में 2002 के बाद सामुदायिक रेडियो नीति के अंतर्गत प्रारम्भ में शैक्षणिक संस्थानों और बाद में गैर-लाभकारी संगठनों को लाइसेंस प्रदान किए गए (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 2006)। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और विकासात्मक मुद्दों को बढ़ावा देना तथा समुदाय-आधारित प्रसारण को प्रोत्साहित करना था।

Rogers (2003) के नवाचार प्रसार सिद्धांत सिद्धांत के अनुसार नई कृषि तकनीकों का प्रसार संचार माध्यमों के माध्यम से अधिक प्रभावी और तीव्र गति से होता है, विशेषकर तब जब सूचना विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो। वहीं सहभागी संचार सिद्धांत यह प्रतिपादित करती है कि विकास तभी स्थायी और समावेशी होता है जब समुदाय स्वयं संचार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी हो (Servaes, 2008)।

कई अध्ययनों में पाया गया है कि सामुदायिक रेडियो किसानों तक मौसम पूर्वानुमान, उन्नत बीज, जैविक खेती, बाजार भाव तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने में सहायक सिद्ध हुआ है (Pavarala - Malik, 2007)। इससे किसानों की निर्णय क्षमता तथा कृषि उत्पादकता में भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

हालाँकि, मध्य भारत के संदर्भ में सामुदायिक रेडियो और आजीविका सशक्तिकरण के बीच संबंध पर अभी भी

सीमित एवं क्षेत्रविशेष आधारित शोध उपलब्ध है। यही इस अध्ययन का प्रमुख शोध-शून्य है, जिसे यह शोध संबोधित करने का प्रयास करेगा।

सैद्धांतिक रूपरेखा

सहभागी संचार सिद्धांत

सहभागी संचार सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक जैन सर्वोस माने जाते हैं, जिन्होंने विकास को एक संवादात्मक और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास ऊपर से नीचे लागू की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समुदाय की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय ज्ञान और सामूहिक निर्णय-निर्माण पर आधारित होना चाहिए।

यह दृष्टिकोण पाउलो फ्रेरे की संवादात्मक शिक्षा की अवधारणा से भी प्रभावित है, जहाँ संवाद के माध्यम से चेतना जागृति को महत्व दिया गया है। सहभागी संचार में सूचना का एकतरफा प्रसार नहीं, बल्कि दो-तरफा संचार, प्रतिक्रिया और सामुदायिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है।

सामुदायिक रेडियो इस सिद्धांत का व्यावहारिक उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्थानीय लोग कार्यक्रम निर्माण, प्रस्तुति और विषय चयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इससे न केवल सूचना का लोकतंत्रीकरण होता है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है।

नवाचार प्रसार सिद्धांत

नवाचार प्रसार सिद्धांत के प्रतिपादक एवेरेट रोजर्स (2003) के अनुसार कोई भी नवाचार समाज में पाँच चरणोंकृ ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अंगीकरण से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों, सामाजिक संरचना और मत-नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

रोजर्स ने अपनाने वालों को पाँच श्रेणियोंकृ नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अंगीकारक, प्रारंभिक बहुमत, देर से अपनाने वाला बहुमत और अंतिम अंगीकारक में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण कृषि नवाचारों जैसे उन्नत बीज, जैविक खेती या नई सिंचाई तकनीकों के प्रसार को समझने में अत्यंत उपयोगी है।

सामुदायिक रेडियो इस सिद्धांत के विभिन्न चरणों को सुगम बनाता है। उदाहरणस्वरूप:

- ज्ञान चरण में यह नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करता है।
- रुचि और मूल्यांकन चरण में विशेषज्ञ वार्ता, किसान अनुभव और चर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से शंकाओं का समाधान करता है।
- परीक्षण और अंगीकरण चरण में सफल किसानों के उदाहरण प्रस्तुत कर विश्वास और प्रेरणा उत्पन्न करता है।

इस प्रकार, सहभागी संचार सिद्धांत और नवाचार प्रसार सिद्धांत दोनों मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि सामुदायिक रेडियो न केवल सूचना प्रसार का माध्यम है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आजीविका सशक्तिकरण की प्रक्रिया में एक सक्रिय उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

शोध पद्धति

शोध प्रकार

यह अध्ययन गुणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। गुणात्मक पद्धति का चयन इसलिए किया गया ताकि सामुदायिक रेडियो की कार्यप्रणाली, स्थानीय सहभागिता और आजीविका सशक्तिकरण से जुड़े अनुभवों को गहराई से समझा जा सके। वर्णनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित रेडियो स्टेशनों की संरचना, कार्यक्रमों की प्रकृति तथा श्रोताओं पर उनके प्रभाव का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह शोध व्याख्यात्मक अभिगम पर आधारित है, जिसमें सामाजिक यथार्थ को प्रतिभागियों के अनुभवों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है।

नमूना चयन

अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण नमूना तकनीक अपनाई गई, जिसके अंतर्गत ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का चयन किया गया जो कृषि, ग्रामीण विकास और सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण करते हैं। चयनित स्टेशन निम्नलिखित हैं:

- **किसान वाणी सिरोंज:** किसान वाणी सिरोंज मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के सिरोंज क्षेत्र से संचालित एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कृषक समुदाय को उपयोगी, व्यवहारिक और समयानुकूल जानकारी उपलब्ध कराना है। यह स्टेशन कृषि, पशुपालन, जैविक खेती, उन्नत बीज, मौसम पूर्वानुमान तथा बाजार भाव जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसकी विशेषता यह है कि कार्यक्रम स्थानीय भाषा और सरल शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे श्रोताओं के लिए समझना आसान हो सके। किसान वाणी सिरोंज किसानों के अनुभव साझा कराने, विशेषज्ञों से सलाह दिलाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का प्रभावी मंच प्रदान करता है साथ ही यह ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को भी कार्यक्रम निर्माण में भागीदारी का अवसर देता है, जिससे सामुदायिक स्वामित्व की भावना विकसित होती है। क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण के कारण यह स्टेशन आजीविका सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- **रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम:** रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में संचालित एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जो क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार करता है। यह स्टेशन बुंदेली भाषा में प्रसारण कर स्थानीय श्रोताओं से निकटता स्थापित करता है। इसके कार्यक्रमों में कृषि तकनीक, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को प्रमुखता दी जाती है। रेडियो बुंदेलखंड लोक संगीत, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर को भी मंच प्रदान करता है, जिससे स्थानीय पहचान सुदृढ़ होती है। यह युवाओं को रेडियो प्रसारण का प्रशिक्षण देकर उन्हें संचार प्रक्रिया में सहभागी बनाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में भी इसकी सक्रिय भूमिका है। इस प्रकार यह स्टेशन क्षेत्रीय विकास और सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है।
- **रेडियो विकल्प:** रेडियो विकल्प मध्य प्रदेश में संचालित एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्गों को अपनी आवाज़ व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। यह शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। स्टेशन की विशेषता यह है कि यह समुदाय के सदस्यों को कार्यक्रम निर्माण और प्रस्तुति में शामिल कर संवादात्मक वातावरण तैयार करता है। फोन-इन कार्यक्रमों और खुली चर्चा के माध्यम से श्रोताओं को सीधे भाग लेने का अवसर मिलता है। रेडियो विकल्प स्थानीय कला, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को भी महत्व देता है, जिससे क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन और समुदाय के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए यह स्टेशन समस्याओं को सामने लाने और समाधान की दिशा में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस प्रकार यह सामुदायिक सशक्तिकरण और आजीविका उन्नयन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित है।

इन स्टेशनों का चयन उनके भौगोलिक क्षेत्र, कृषि-प्रधान श्रोता वर्ग तथा स्थानीय समुदाय से सक्रिय जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस चयन से अध्ययन को क्षेत्रीय विविधता और तुलनात्मक विश्लेषण की दृष्टि प्राप्त हुई।

समंक संकलन के उपकरण

- अध्ययन में बहु-स्रोत पद्धति अपनाई गई ताकि डेटा की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित की जा सके।
- **अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार:** स्टेशन प्रबंधकों, आरजे तथा चयनित किसानों से साक्षात्कार किए गए। पूर्व-निर्धारित प्रश्नों के साथ आवश्यकतानुसार पूरक प्रश्न पूछे गए, जिससे अनुभव और दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके।
 - **अंतर्वस्तु विश्लेषण:** तीन माह की प्रसारण सामग्री का अध्ययन किया गया। कृषि, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों की आवृत्ति और प्रस्तुति शैली का विश्लेषण किया गया।
 - **द्वितीयक स्रोत:** सरकारी रिपोर्ट, नीति दस्तावेज और शोध लेखों का उपयोग संदर्भगत आधार मजबूत करने और प्राथमिक निष्कर्षों की पुष्टि के लिए किया गया।

डेटा विश्लेषण

संकलित डेटा का विश्लेषण विषयगत विश्लेषण पद्धति से किया गया। साक्षात्कार और कार्यक्रम सामग्री को कोडिंग के माध्यम से प्रमुख विषयों में वर्गीकृत किया गया। समान विचारों को समेकित कर प्रमुख प्रवृत्तियों और प्रभावों की पहचान की गई। निष्कर्षों की सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए डेटा का पुनर्पाठ और तुलनात्मक परीक्षण किया गया।

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

कृषि तकनीकी ज्ञान का प्रसार

विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि तीनों सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में कृषि आधारित कार्यक्रमों की प्रमुखता रही। औसतन 45-60 प्रतिशत प्रसारण समय कृषि, उन्नत बीज, जैविक खेती, पशुपालन तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित विषयों को दिया गया। साक्षात्कारों में किसानों ने बताया कि नियमित जानकारी से नई तकनीकों को अपनाने में सहजता आई तथा उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ।

सारणी 1: कृषि कार्यक्रमों का प्रभाव

संकेतक	किसान वाणी सिरोंज	रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम	रेडियो विकल्प
कृषि कार्यक्रम (प्रतिशत)	60 प्रतिशत	52 प्रतिशत	45 प्रतिशत
उन्नत बीज अपनाने वाले किसान (प्रतिशत)	48 प्रतिशत	41 प्रतिशत	37 प्रतिशत
जैविक खाद प्रयोग में वृद्धि (प्रतिशत)	44 प्रतिशत	39 प्रतिशत	33 प्रतिशत
कीट प्रबंधन तकनीक अपनाना (प्रतिशत)	46 प्रतिशत	38 प्रतिशत	35 प्रतिशत

(स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम विश्लेषण, 2025)

जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण विषयक कार्यक्रमों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संरक्षण पर आधारित प्रसारणों ने समुदाय को स्थानीय संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया।

सारणी 2: जल संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव

संकेतक	किसान वाणी सिरोंज	रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम	रेडियो विकल्प
जल संरक्षण कार्यक्रम (प्रतिशत)	22 प्रतिशत	30 प्रतिशत	18 प्रतिशत
वर्षा जल संचयन अपनाने वाले (प्रतिशत)	28 प्रतिशत	40 प्रतिशत	21 प्रतिशत
सूक्ष्म सिंचाई तकनीक उपयोग (प्रतिशत)	25 प्रतिशत	36 प्रतिशत	19 प्रतिशत
तालाब/कुंआ पुनर्जीवन पहल (प्रतिशत)	18 प्रतिशत	32 प्रतिशत	15 प्रतिशत

(स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम विश्लेषण, 2025)

महिला सशक्तिकरण

महिला स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया। कई महिलाओं ने रेडियो कार्यक्रमों से प्रेरित होकर आय-वृद्धि गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया।

सारणी 3: महिला सहभागिता एवं प्रभाव

संकेतक	किसान वाणी सिरोंज	रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम	रेडियो विकल्प
महिला केंद्रित कार्यक्रम (प्रतिशत)	20 प्रतिशत	24 प्रतिशत	18 प्रतिशत
SHG से जुड़ने वाली महिलाएँ (प्रतिशत)	27 प्रतिशत	33 प्रतिशत	22 प्रतिशत
आय-वृद्धि गतिविधि शुरू (प्रतिशत)	23 प्रतिशत	29 प्रतिशत	19 प्रतिशत
नेतृत्व भूमिका में वृद्धि (प्रतिशत)	21 प्रतिशत	26 प्रतिशत	17 प्रतिशत

(स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम विश्लेषण, 2025)

सामाजिक पूंजी निर्माण

रेडियो ने स्थानीय संवाद, सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूत किया। फोन-इन कार्यक्रमों और खुली चर्चाओं ने सामुदायिक एकजुटता को प्रोत्साहित किया।

सारणी 4: सामाजिक पूंजी निर्माण संकेतक

संकेतक	किसान वाणी सिरोंज	रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम	रेडियो विकल्प
सामुदायिक चर्चा कार्यक्रम (प्रतिशत)	26 प्रतिशत	31 प्रतिशत	24 प्रतिशत
फोन-इन सहभागिता दर (प्रतिशत)	34 प्रतिशत	38 प्रतिशत	29 प्रतिशत
सामूहिक बैठक में वृद्धि (प्रतिशत)	42 प्रतिशत	47 प्रतिशत	36 प्रतिशत
सामुदायिक सहयोग की अनुभूति (प्रतिशत)	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	44 प्रतिशत

(स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम विश्लेषण, 2025)

चारों सारणियों के समेकित विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसान वाणी सिरोंज, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम तथा रेडियो विकल्प अपने-अपने क्षेत्रीय संदर्भ में विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। कृषि कार्यक्रमों के प्रतिशत और तकनीक अपनाने के आँकड़े संकेत देते हैं कि जहाँ कृषि विषयक प्रसारण अधिक है, वहाँ नवाचारों का अंगीकरण भी अपेक्षाकृत अधिक देखा गया। जल संरक्षण से संबंधित सारणी विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है, जो स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। महिला सशक्तिकरण संबंधी आँकड़े बताते हैं कि महिला-केंद्रित कार्यक्रमों की उपलब्धता से स्वयं सहायता समूहों में सहभागिता और आय-वृद्धि गतिविधियों में वृद्धि हुई है। सामाजिक पूंजी निर्माण के संकेतक यह दर्शाते हैं कि

संवादात्मक कार्यक्रमों ने सामुदायिक सहयोग, सहभागिता और विश्वास को सुदृढ़ किया। समग्र रूप से आँकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि सामुदायिक रेडियो बहुआयामी ग्रामीण सशक्तिकरण में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

चर्चा

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक रेडियो सहभागी संचार मॉडल का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत करता है। यह केवल सूचना प्रसारित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि संवाद, सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। कृषि नवाचारों के प्रसार, जल संरक्षण की जागरूकता और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई।

हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण कई स्टेशनों को तकनीकी उन्नयन और कार्यक्रम विस्तार में कठिनाई होती है। सीमित प्रसारण क्षेत्र (कवरेज) के कारण संदेश सभी लक्षित समुदायों तक नहीं पहुँच पाता साथ ही तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी भी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। इन चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय स्तर पर इन स्टेशनों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता उल्लेखनीय है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से यह अध्ययन दर्शाता है कि मध्य भारत में सामुदायिक रेडियो ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। यह कृषि उत्पादकता में सुधार, महिला उद्यमिता के विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सकारात्मक योगदान दे रहा है। सहभागी संचार के सिद्धांत पर आधारित यह माध्यम समुदाय को केवल श्रोता नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बनाता है।

नीतिगत स्तर पर आवश्यक है कि सामुदायिक रेडियो को कृषि विस्तार सेवाओं, ग्रामीण विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन से अधिक समन्वित रूप में जोड़ा जाए, ताकि इसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक हो सके।

सुझाव

- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया) से जोड़ा जाए, ताकि युवा वर्ग तक पहुँच बढ़ सके।
- कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित कर विशेषज्ञता और वैज्ञानिक जानकारी को कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- महिला और युवा सहभागिता को प्राथमिकता देकर उन्हें कार्यक्रम निर्माण और प्रबंधन में अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ।
- दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वैकल्पिक एवं स्थायी वित्तीय मॉडल विकसित किए जाएँ, जैसे सामुदायिक सहयोग, स्थानीय विज्ञापन और परियोजना आधारित सहयोग।

इस प्रकार, सामुदायिक रेडियो को सुदृढ़ नीतिगत समर्थन और संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत की जनगणना. (2011) ग्रामीण जनसंख्या सांख्यिकी. भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. Fraser, C. and Restrepo-Estrada, S. (2001) सामुदायिक रेडियो हैंडबुक. यूनेस्को।
3. Melkote, S. R. and Steeves, H. L. (2015) विकास हेतु संचार: सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांत एवं व्यवहार. सेज पब्लिकेशन्स, कैलिफोर्निया।

4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (2006) सामुदायिक रेडियो नीति दिशानिर्देश. भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. Pavarala, V. and Malik, K. K. (2007) अन्य आवाज़ें: भारत में सामुदायिक रेडियो के लिए संघर्ष. सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, नई दिल्ली।
6. Rogers, E. M. (2003) नवाचारों का प्रसार (5वाँ संस्करण), फ्री प्रेस, न्यूयार्क।
7. Servaes, J. (2008) विकास और सामाजिक परिवर्तन हेतु संचार. सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, नई दिल्ली।
8. Singhal, A. and Rogers, E. M. (2001) भारत की संचार क्रांति: बैलगाड़ी से साइबर बाज़ार तक. सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, नई दिल्ली।
9. Kumar, K. J. (2010) भारत में जनसंचार (चौथा संस्करण) जयको पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
10. Dutta, M. J. (2011) सामाजिक परिवर्तन का संचार: संरचना, संस्कृति और अभिकरण. रूटलेज इंडिया, नई दिल्ली।
11. Manyozo, L. (2012) मीडिया, संचार और विकास: तीन दृष्टिकोण. सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, नई दिल्ली।
12. Prasad, K. (सम्पा.) (2005) विकास हेतु संचार: सिद्धांत और क्रियान्वयन का पुनर्निर्माण. बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली।

---==00==---